

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 21 दिसंबर 2025 वर्ष-8, अंक-294 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट, पायलट सस्पेंड

■ यात्री का दावा: मामला खत्म करने का दबाव बनाया



एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर शुक्रवार को ऑफ-ड्यूटी पायलट ने एक यात्री से मारपीट की। इस घटना के बाद यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए हादसे की जानकारी शेयर की। साथ ही पायलट के कपड़ों और अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर भी पोस्ट की। घटना के सामने आते ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था। वह दूसरी फ्लाइट का पैसेंजर था। हमने उसे हटा दिया है, जांच पूरी होने पर कार्रवाई होगी घटना के बाद यात्री ऑकित दीवान ने एक पोस्ट लिखा। इसमें कहा कि मुझ पर मामला खत्म करने का दबाव बनाया गया। जबरदस्ती लेटर लिखवाया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ती। ऑकित ने ये भी बताया कि मेरी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को पिटने और मेरे खून से सने चेहरे को देखा। इसके बाद से वह सड़मे में है। पैसेंजर ने शनिवार को एक और पोस्ट में पायलट का वीडियो शेयर किया है।

असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत

■ ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे



एजेंसी
गुवाहाटी। असम के होजाई जिले में शनिवार सुबह हाथियों का एक झुंड सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में सात हाथियों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में ट्रेन का इंजन और पांच कोच भी पटरी से उतर गए। यह हादसा सुबह 2:17 बजे चांगजुराई गांव के पास हुई। शुरूआत में आठ हाथियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि एक हाथी का बच्चा जिंदा है और गंभीर रूप से घायल है। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। नगांव के डिबीजल फॉरेस्ट ऑफिसर सुहास कदम ने बताया कि इलाके में घना कोहरा होने के कारण यह हादसा हुआ होने की आशंका है। मृत हाथियों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय पशु चिकित्सक घायल हाथी का इलाज कर रहे हैं। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिजल किशोर शर्मा ने बताया कि हादसा गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर दूर लुमिडिंग डिबीजन के तहत जमुनामुख-कापुर सेक्शन में हुआ। हादसे वाली जगह अधिसूचित हाथी कॉरिडोर नहीं है।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर जनता से सुझाव मांगे, जानिए क्या है मकसद

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत सरकार ने बजट 2026 के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश के लिए नए नियम और योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। MyGovIndia के एक पोस्ट के अनुसार, सरकार ने लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने MyGovIndia पर लिखा, "जनता की राय से बजट का निर्माण। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय



विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान दें।" इस संदेश में सभी को MyGov वेबसाइट पर जाकर अगले वर्ष के लिए नए बजट में किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले पिछले महीने, केंद्रीय वित्त और

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित

गिल-जितेश बाहर, ईशान और रिकू की वापसी

एजेंसी
नई दिल्ली। गत चैंपियन भारत सूर्यकुमार यादव की अगुआई में अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप में खिताब का बचाव करने उतरेगा। अजीत अगरकर की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक में टीम का चयन किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली टी20 सीरीज में भी यही टीम खेलेंगी। भारत ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टॉफी अपने नाम की थी। भारत इस टूर्नामेंट

में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा। यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। अब तक कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव नहीं कर सकी है, ऐसे में टीम इंडिया के पास घरेलू जमीन पर यह तिलिस्म तोड़ने का सुनहरा अवसर होगा। भारत ने टी20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है उसमें शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। गिल अभी तक टीम के उपकप्तान थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेल को सौंपी गई है। गिल टी20 में अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे। वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और रिकू सिंह की टीम में वापसी हुई है। ईशान भारत के लिए आखिरी बार 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के



खिलाफ खेले थे। यह उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच भी था। ईशान इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुने गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। दौरे के बीच में ईशान वापस आ गए थे। घरेलू क्रिकेट की जगह आईपीएल को तरजीह देने के विवाद के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब दो साल बाद उनकी टीम में वापसी हुई है। दूसरी ओर, रिकू एशिया

कप का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मौका नहीं मिला था। शुभमन गिल की जगह अक्षर पटेल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है। अक्षर इससे पहले भी टी20 में उपकप्तान की भूमिका निभा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईशान किशन की टीम में वापसी हो गई है। ईशान किशन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में 101

रन की पारी खेली थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका बल्ला जमकर चला था। हालांकि, ईशान के शामिल होने से जितेश शर्मा टीम में जगह नहीं बना पाए हैं और उन्हें बाहर होना पड़ा है। टीम का एलान करते वक्त अजीत अगरकर ने बताया कि संजू सैमसन विकेटकीपर होंगे। गिल के बाहर होने से अब ये तय हो गया है कि अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने उतरेंगे। सैमसन और अभिषेक की सलामी जोड़ी काफी सफल रही है और ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में भी देखने मिला था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की पुष्टि की है कि टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कोई स्टैंडबाई खिलाड़ी नहीं होगा।

पीएम मोदी बोले: 'बंगाल को जंगलराज से मुक्त होना होगा'

नादिया रेली को कोलकाता से पीएम मोदी ने किया वरुअली संबोधित

एजेंसी
कोलकाता/गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तहरेपुर हेलीपैड पर उतरने की कोशिश में असफल रहे। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे पीएम का हेलीकॉप्टर कुछ समय हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कोलकाता हवाई अड्डे लौट गया। उन्होंने एयरपोर्ट से ही वरुअली संबोधन किया। उन्होंने खराब मौसम के कारण रेली स्थल तक नहीं पहुंच पाने पर लोगों से माफी भी मांगी। पीएम मोदी ने सभा को वरुअली संबोधन में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मंत्र था। पीएम मोदी ने



कहा वंदे मातरम को राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने बंगाल समेत पूरे देश के लोगों को बड़ी राहत दी है और दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान देशभर के लोग इससे काफी लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है। पीएम ने कहा कि गंगा

बिहार से होकर बंगाल तक जाती है और बिहार ने बंगाल को रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को जंगलराज से मुक्त होना होगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वे पूरे दिल से बंगाल के लोगों के लिए समर्पित हैं और राज्य के लिए फंड और नीतियों की कोई कमी नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाएं राज्य सरकार की वजह से लंबित पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी भाजपा का विरोध करना चाहती है तो करे, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए विकास को रोके जाने की बात समझ से

बाहर है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा को एक मौका दें, डबल इंजन सरकार बनने दें और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पहले 3,200 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी सुबह करीब 10.40 बजे दिल्ली से कोलकाता पहुंचे थे। वहां से हेलिकॉप्टर से तहिरपुर खाना हुए। लेकिन, घने कोहरे के कारण हेलिकॉप्टर कुछ देर तक हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कोलकाता लौट गया। गौरतलब है कि अपने बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री करीब 3,200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बजागुली-कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे फोर-लेन का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात-बरजागुली सेक्शन के फोर-लेन का शिलान्यास किया।

'प्रधानमंत्री ने शांति बिल जबरन क्यों पास कराया

■ हमें पता चल गया है', सरकार पर कांग्रेस का निशाना

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि परमाणु विधेयक SHANTक बिल को संसद में सिर्फ इसलिए जबरन पारित कराया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक समय के अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल कर सकें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। जयराम रमेश ने कहा कि शांति बिल 'सिविल लार्गबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज एक्ट' के मुख्य प्रावधानों को खत्म करता है और यह एक चिंता का विषय है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026 में भी इसे लेकर चिंता जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी-अभी अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे लेकर जयराम रमेश ने 'एक्स पर साझा एक पोस्ट' में कहा, 'यह एक्ट 3,100 पन्नों का है। पेज 1,912 पर न्यूक्लियर



लार्गबिलिटी नियमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त मूल्यांकन का जिफ्र है। अब हमें पक्का पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते की शुरूआत में संसद में शांति बिल को जल्दबाजी में पास कराया, जिसने सिविल लार्गबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज एक्ट, 2010 के मुख्य प्रावधानों को खत्म कर दिया।' कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी एक्ट की एक कॉपी लगाते हुए कहा, 'यह उनके एक समय के अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल करने के लिए था।'

दिल्ली में टंड-प्रदूषण का डबल अटैक: घने कोहरे से थमी रफ्तार

एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी में स्थानीय कारकों के कारण अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा की गति धीमी होने के कारण लगातार 5वें दिन भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। शनिवार सुबह की शुरूआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। साथ ही स्मॉग की घनी चादर भी दिखाई दी। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। इससे लोगों को आंखों में जलन व सांस के मरीजों को परेशानी हुई। दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर



क्वालिटी अलर्ट वॉरनिंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, शनिवार सुबह राजधानी का औसत एअर क्वालिटी इंडेक्स (एयूआई) 376 दर्ज किया गया है। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में एयूआई 400 पर दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे को आंखों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एयूआई 362, आनंद विहार में एयूआई 428, अशोक विहार में 412, आया नगर में 298, बवाना में 365, बुराड़ी में 381, चांदनी चौक इलाके में 410 एयूआई दर्ज किया गया है।

5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट

बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे, टॉप 6 राज्यों में यूपी-एमपी और बंगाल

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच सालों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में 1.04 करोड़ कार्ड डिलीट हुए हैं। दूसरे नंबर पर यूपी है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कुल हटाए गए जॉब कार्ड में बिहार और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 44% है। बिहार-यूपी के अलावा जिन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड

डिलीट किए गए, उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। यह जानकारीयां ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश्वर पासवान ने राज्यसभा में सांसद तिलेश शिवा के सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि जितने भी जॉब कार्ड डिलीट हुए, वे फजी, डुप्लीकेट या गलत जानकारीयों वाले कार्ड थे और यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है। मंत्री ने बताया कि जिन परिवारों ने स्थायी रूप से पलायन कर लिया है, जिन ग्राम पंचायतों का शहरीकरण हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का



एकमात्र सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में भी कार्ड डिलीट किए गए हैं। सरकार ने बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 25 जनवरी 2025 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी। केंद्र के

मुताबिक, अगर किसी भी तरह का कन्स्यूजन होता है इन रडब को देखा जा सकता है। 1 से 19 दिवस तक चले, संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन

(ग्रामीण), 2025 (वीवी-जी राम जी) करने वाला बिल पास हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे संसद में पेश किया था। ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को रिप्लेस करेगा। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित बिहार के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इसके तहत काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। इस मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया।

'वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आया

अब कोई मर्जी नहीं थोप सकता' विदेश मंत्री जयशंकर का बयान



एजेंसी
नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बड़े बदलाव से गुजर रहा है और अब ताकत के कई केंद्र उभरे हैं। पुणे में सिम्ब्यायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब सभी मुद्दों पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकता।' उन्होंने कहा, 'इसका मतलब यह भी है कि अब दुनिया के देशों के बीच एक स्वाभाविक मुकाबला है और यह अपना संतुलन बनाता है। शक्ति और प्रभाव के कई केंद्र उभरे हैं।' उन्होंने कहा कि शक्ति के विचार को कई परिभाषाएं हैं, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, सेना, संसाधन, तकनीक और टैलेंट शामिल हैं। यह इसे एक खास तौर पर जटिल बनाते हैं। जयशंकर ने कहा, 'यह पहचानना भी जरूरी है कि वैश्विक शक्तियां अब सांख्यिकीय होने से शक्ति नहीं हैं। वैश्वीकरण ने हमारे सोचने और काम करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। जयशंकर ने कहा, 'हमारे जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर

चलना है, तो उसे महत्वपूर्ण और आधुनिक मैयूफेक्चरिंग विकसित करनी चाहिए।' विदेश मंत्री ने कहा जब मैं आपके समय में था, तब दुनिया अलग थी और कम जटिल थी, लेकिन दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजरी है और हमारे समाज और देश में भी बदलाव हुए हैं। अब नई पीढ़ी पर जिम्मेदारी है कि वे विकसित भारत की जिम्मेदारी लें।' बांग्लादेश के हालात पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, 'बांग्लादेश बनने के कुछ साल बाद, हमारे सामने पाकिस्तान के साथ-साथ पश्चिम और चीन भी थे। इसके जवाब में, भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मजबूत रणनीतिक रिश्ता बनाया। यह सुधारों से पहले का दौर था, जिसमें कम आर्थिक विकास, कमी, लाइसेंसिंग कंट्रोल और सीमित विदेशी व्यापार था। हमारे समाज और दुनिया के साथ हमारे संबंध आज से बहुत अलग थे।' डॉ.

बेलगाम बांग्लादेश की अशांति भारत के लिये खतरा

(लेखक- –ललित गर्ग)

बांग्लादेश में बीते कुछ समय से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वे किसी एक देश की आंतरिक समस्या भर नहीं रह गए हैं, बल्कि दक्षिण एशिया की समूची भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चेतावनी बनते जा रहे हैं। युवा छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह ढाका सहित कई शहरों में हिंसा भड़की, उसने यह उजागर कर दिया कि मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार न तो कानून का शासन स्थापित कर पा रही है और न ही समाज को उन्माद व कट्टरता से बचाने में सक्षम दिखाई देती है। सड़कों पर उग्र भीड़, अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले, हिन्दू धर्म-स्थलों को ध्वस्त करना, मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में आगजनी, पत्रकारों पर हमले और असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिशें यह संकेत देती हैं कि बांग्लादेश तेजी से अराजकता के दलदल में धंसता जा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए जितनी भयावह है, उतनी ही खतरनाक क्षेत्रीय शांति के लिए भी है।

इस पूरे परिदृश्य का सबसे चिंताजनक एवं त्रासद पहलू ‘भारत विरोधी नैरेटिव’ का सुनियोजित एवं षडयंत्रपूर्ण निर्माण है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए बिना किसी ठोस जांच के भारत पर आरोप मढ़ना और उसके बाद भारतीय मिशनों को निशाना बनाने की कोशिशें यह बताती हैं कि हिंसा केवल स्वतःस्फूर्त जनाक्रोश नहीं, बल्कि एक सुविचारित राजनीतिक और वैचारिक साजिश का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, कुछ कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोध को एक आसान औजार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इससे न केवल भीड़ को भड़काया जाता है, बल्कि आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने का रास्ता भी मिल जाता है। अंतरिम सरकार की निष्क्रियता या मीन सहमति इस आशंका को और मजबूत करती है कि वह या तो इन ताकतों पर नियंत्रण खो चुकी है या फिर उनसे समझौता कर चुकी है। इसमें सबसे

घातक है पाकिस्तान का साजिशपूर्ण तरीके से भारत विरोध को हवा देना।

भारत द्वारा अपने वीजा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करना और बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब करना इस पृष्ठभूमि में एक आवश्यक और संतुलित कूटनीतिक कदम कहा जा सकता है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विदेशी राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ढाका में भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिशें और वहां प्रशासन की दुलमुल प्रतिक्रिया यह दर्शाती हैं कि अंतरिम सरकार इस बुनियादी दायित्व को निभाने में विफल रही है। कूटनीति केवल सौहार्द की भाषा नहीं होती, बल्कि यह स्पष्ट संदेश देने का माध्यम भी होती है कि भारत अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा के प्रश्न पर किसी तरह की उदासीनता स्वीकार नहीं कर सकता।

इस अशांति का सबसे दर्दनाक और संवेदनशील पक्ष बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की बिगड़ती स्थिति है। कथित ईशनिंदा के आरोपों में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या इस बात का प्रमाण है कि कट्टरपंथी तत्वों को अब प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया है। जब न्याय भीड़ के हाथों में चला जाए और सरकार अल्पसंख्यक अधिकारों पर केवल औपचारिक बयान जारी करती रहे, तो यह लोकतांत्रिक राज्य की आत्मा पर सीधा प्रहार होता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी भी इस संदर्भ में कई सवाल खड़े करती है। मानवाधिकारों और अल्पसंख्यक संरक्षण की दुहाई देने वाले वैश्विक मंच तब मीन क्यों हो जाते हैं, जब यह उल्लंघन राजनीतिक या राजनीतिक समीकरणों के भीतर घटित होते हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र और सलाहकार साजीब वाजेद जॉय का यह कथन कि बांग्लादेश की आग से भारत अछूता नहीं रह सकता, केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच हजारों किलोमीटर की साझा सीमा, सांस्कृतिक-सामाजिक रिश्ते और आर्थिक निर्भरता ऐसी है कि ढाका की

अस्थिरता का असर स्वाभाविक रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ेगा। अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी नेटवर्कों की सक्रियता और सीमा पार अपराधों का खतरा इस अस्थिरता के साथ बढ़ता ही जाएगा।

आगामी फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव बांग्लादेश के लिए एक अवसर हो सकते थे, जिससे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए स्थिरता की ओर लौट सके। लेकिन मौजूदा हालात में चुनाव की पारदर्शिता और शांति पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतें जनभावनाओं को भड़काकर हिंसा का माहौल बनाए रखने में जुटी हैं, ताकि सत्ता का संतुलन अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। अंतरिम सरकार का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करे, लेकिन अब तक के संकेत बताते हैं कि वह इस चुनौती के सामने कमजोर साबित हो रही है। इस पूरे परिदृश्य में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाना और भारत के पड़ोस में अशांति, हिंसा एवं आतंक के बीज बोना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों और भारत विरोधी तत्वों को वैचारिक, नैतिक और कभी-कभी परोक्ष समर्थन मिलना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह एक अवसर की तरह है, जहां वह बांग्लादेश की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोल सकता है। सोशल मीडिया अभियानों से लेकर दुष्प्रचार तक, कई संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी भावना की पीछे पाक की सोच भी सक्रिय है। यह वही रणनीति है, जिसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और अपने ही देश में अपनाकर पूरे क्षेत्र को अस्थिरता के गर्त में धकेल दिया।

भारत का रुख हमेशा से एक स्थिर, समृद्ध और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के पक्ष में रहा है। आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और मानवीय सहायता के माध्यम से भारत ने यह साबित किया है कि वह अपने पड़ोसी के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है, न कि विधि की जानकारी हमको मिलती है।श्रीकृष्ण ने परमात्म निमित्त बन अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय बताया है कि, कैसे मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए ध्यान क्रिया की जानी चाहिए।

गीता के अनुसार, ध्यान करने के लिए सबसे पहले किसी शुद्ध स्थान पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि, ना ही स्थान बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। आसन पर बैठने के बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और इंद्रियों और मन को नियंत्रण में लाने का अभ्यास करना चाहिए।

ध्यान करने के लिए सिर व गले को समान और अचल रखते हुए सुखासन में योगी को बैठना चाहिए। बाहरी चीजों से ध्यान को हटाकर नासिका के अग्र भाग यानि दोनों भौंहों के बीच जहां आत्मा निवास करती है,के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तत्पश्चात सभी प्रकार के विषयों से मन को हटाकर नेत्रों को भुकुटी के मध्य में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद प्राण और अपान वायु को सम करना चाहिए।

इसके बाद मन के सभी विकारों से दूर होकर, उत्तेजनारहित और शांति के साथ ध्यान और ईश्वर के चिंतन में बैठे रहना चाहिए। इस तरह से निर्मल और निर्विकार व्यक्ति परमतत्व का ध्यान करते हुए आनंद की अंतिम सीमा को प्राप्त करता है और उसे शांति मिलती है। गीता के अनुसार, ध्यान उसका ही सिद्ध होता है, जो न अधिक खाता है और ना ही अधिक भूखा रहता है। अधिक जगाने या सोने वाले को भी ध्यान की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सुख में अत्यधिक खुश और दुःख में ज्यादा दुःखी होने वाला व्यक्ति भी ध्यान को सिद्ध नहीं कर पाता। गीता में बताया गया है कि, जो व्यक्ति उचित आहार-विहार करता है, उसी को ध्यान-योग में सिद्धि प्राप्त होती है।

गीता में बताई गई इन शिक्षाओं को जीवन में आजमाकर हम ध्यान कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। ध्यान

वर्चस्ववादी। लेकिन यदि ढाका की अंतरिम सरकार अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक हिंसा के लिए होने देती है, तो द्विपक्षीय संबंधों में आई दरार को भरना बेहद कठिन हो जाएगा। यह केवल कूटनीति का प्रश्न नहीं, बल्कि विश्वास और साझी सुरक्षा का भी मुद्दा है। अंतरिम सरकार के सामने अब दो ही रास्ते हैं। पहला, वह इन कार्रवाई कर यह साबित करे कि वह किसी कट्टरपंथी विचारधारा की बंधक नहीं है और कानून का शासन बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, वह निष्क्रियता और तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हुए देश को और गहरे संकट में धकेल दे। इतिहास बताता है कि दूसरा रास्ता अंततः लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने तीनों को नष्ट कर देता है। बांग्लादेश एक ऐसे समय अराजकता में डूबा है, जब वह चुनाव सन्निकट है। अब चुनावों में पाकि एवं लोकतांत्रिक तरीके से होना संदिग्ध है। इन चुनावों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भाग लेने से रोकना एवं पाकिस्तानपरस्त जमाते इस्लामी समेत अन्य कट्टरपंथी ताकतों को भी चुनाव मंचों की छूट देना, अंतरिम युनुस सरकार की कुवेष्ट है। सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि चुनाव के बाद वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों के वर्चस्व वाली ऐसी सरकार अस्तित्व में आ सकती है, जो भारत के खिलाफ खुलकर काम करते हुए अल्पसंख्यकों के संहार को अंजाम देगी। भारत के लिए इसीलिये भी यह समय केवल चिंता व्यक्त करने का नहीं, बल्कि सतर्क और सक्रिय कूटनीति अपनाने का है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैश्विक मंचों पर बांग्लादेश की ताजा घटनाओं को स्पष्टता और तथ्यों के साथ उठाना आवश्यक है। पड़ोस में लगी यह आग यदि समय रहते नहीं बुझाई गई, तो इसकी तपिश केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को झुलसा सकती है। स्थिरता, लोकतंत्र और सह-अस्तित्व की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता को एक चेतावनी की तरह लिया जाए, न कि एक क्षणिक राजनीतिक उथल-पुथल के रूप में।

संपादकीय

चूक से हादसे

लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान तार्किक ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। निश्चय ही यदि वाहन चालकों को सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए और हम जिम्मेदारी-सावधानी से वाहन चलाएं तो हर साल हजारों जिनदगियां बचायी जा सकती हैं। भारत में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामले में हम अव्वल हैं। विडंबना देखिए कि एक साल में देश के भीतर करीब पांच लाख सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो छोटे शहरों व भीतरी इलाकों में होते तो हैं, लेकिन दर्ज नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोग इन हादसों में मारे जाते हैं। लाखों लोग इन हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों के बाद जीवनपर्यंत सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दुखद स्थिति यह भी है कि मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। एक आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 66 फीसदी लोग 18 से 34 साल के बीच होते हैं। जो अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। फलतः हादसे के बाद कई परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ओवर स्पीडिंग से 68 फीसदी से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं निर्धारित स्पीड से अधिक तेजी से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ही 68 फीसदी मौतें भी होती हैं। निश्चित रूप से ये हादसे व मौतें मानवीय व्यवहार की कमजोरी से जुड़े हैं। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हुआ है तो बेहतर सड़कों में वाहन चालकों की गति अनियंत्रित हो चली है। जो कालांतर सड़क हादसों की वजह बनती है। यह विडंबना है कि हम अकसर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी हेलमेट पहनने से परहेज करती है। यह जानते हुए कि हादसों में सिर की चोट जानलेवा बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण 54,568 लोगों की मौत हुई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने से 16 हजार से अधिक यात्रियों की जान गई। इन हादसों की एक बड़ी वजह ऐसे अकुशल चालकों का होना भी था, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार चालकों में 33,827 ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। देश में बड़ी संख्या ऐसे चालकों की होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते। इसके अलावा जुगाड़ से ले-देकर लाइसेंस बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वे वाहन चलाने की पर्याप्त योग्यता व अनुभव के बिना ही चालक बन बैठते हैं। हाल के वर्षों में नशे की हालात में वाहन चलाने का फैशन भी बना है। कई हादसों के बाद खुलासा हुआ कि फलां चालक नशे में धुत था। हालांकि, महानगरों व शहरों में नाका लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पकड़-धकड़ की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर ऐसी जांच बड़े पैमाने पर होती नजर नहीं आती। वहीं ऐसे चालकों की भी कमी नहीं है, जो फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं। जिससे लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निश्चित रूप से फोन पर बातचीत करता व्यक्ति भावावेश में उद्बेलित हो सकता है, जिससे वाहन चलाने की गुणवत्ता बाधित होती है। वाहन को सुरक्षित ढंग से चलाना भी एक कला है। चालक का मानसिक रूप से शांत होना भी जरूरी है। हाल के दिनों में सड़कों की बेहतर स्थितियों में लोगों में रात में सफर करने का रुझान बढ़ा है। गाहे-बगाहे चालक को झपकी लगने पर दुर्घटना होने के समाचार अकसर सुनने में आते हैं। निश्चित रूप से सड़क हादसों के मूल में तकनीकी कारण और सड़कों के डिजाइन व गुणवत्ता की भी भूमिका होती है।



न्याय की देवी की आँखो से काली पड़ी हटा ली गई है। न्याय एवं समरथ के पक्ष में होगा। भारत में सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ फैसला करने वाले जज अब दंडित होंगे। राजस्थान की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोल खदान को लेकर एक संयुक्त कंपनी बनाई थी। इस कंपनी ने परिवहन के नाम पर अनुबुध के विपरीत राजस्थान सरकार से 1400 करोड़ रुपए की मांग परिवहन के नाम पर की थी। राजस्थान सरकार यह भुगतान करने के लिए तैयार हो गई थी। इसी बीच देश के सबसे बड़े पूंजीपति की कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए की राशि का ब्याज भी मांग लिया। कंपनी खुद ही मामले को न्यायालय में ले गई। न्यायालय ने जब सारे एग्जिमेंट का अध्ययन किया, तब न्यायाधीश ने यह सुनिश्चित किया, कि 1400 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है, वह अनैतिक और अवैधानिक है। कोर्ट ने राज्य सरकार की मंशा के खिलाफ फैसला सुनाते हुए संयुक्त कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इससे सरकार और देश के सबसे बड़े पूंजीपति दोनों ही नाराज हो गए। खामियाजा जज महोदय को भुगतना पड़ा। यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि इसी तरह के कई मामले हाईकोर्ट जजों के साथ पूर्व में हो चुके हैं। जिन जजों ने सरकार की मंशा के विपरीत फैसला देने का साहस किया है, उन जजों को दंड स्वरूप डिमोशन के साथ ट्रांसफर करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिस जज ने यह साहसिक सही फैसला सुनाया, उसे दंड मिला। जो दोषी था, उसे जजों के ट्रांसफर से न्याय की अनुभूति हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्तमान में जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के जज निडर होकर न्याय कर सकते हैं? न्यायापालिका सत्ता के प्रभाव और पूंजीप तियों की हैसियत के दबाव में फैसला करेगी।

न्यायव्यवस्था लोकतंत्र का वह स्तंभ है जिस पर आम नागरिक का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब कार्यपालिका और विधायिका पर सवाल उठते हैं, तब जनता की आखिरी उम्मीद अदालत से होती है।

कठिन काम

एक लड़का महात्मा के पास पहुंचा। लड़का बड़ा शैतान था, उसको देखते ही महात्मा ने भाप लिया। इसलिए मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रतिबोध देने के लिए महात्मा बोले- बच्चे! तुम तो बड़े तेज दिखाई देते हो। वह अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ और कहने लगा – स्कूल में सब लड़के मुझसे डरते हैं। महात्मा- अच्छा, तुम सरल काम करना चाहते हो या कठिन? लड़का- मैं कठिन से कठिन काम करना चाहता हूं। महात्मा- तुम्हें कोई गाली दे तो तुम बया करोगे? लड़का- मुझे कोई एक गाली देगा तो उसको दस गाली सुनाऊंगा। महात्मा- ऐसा करना सरल है या कठिन?



सामने वाला बच्चा यह देखकर दंग रह गया। वह बोला- भैया! मैंने अच्छा नहीं किया, क्षमा करना। ऐसा सुनकर उसने संकल्प कर लिया कि जीवन की स्वस्थता के लिए वह हंसे ही काम करेगा।

खुली आंख से देखकर फैसला करें जज

(लेखक-सनत जैन)

राजस्थान में हाल ही में आए एक न्यायिक फैसले ने देशभर में बहस छेड़ दी है। क्या सही न्याय करने पर अब जजों को दंड मिलेगा? एक दर्जन से ज्यादा जजों को लेकर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें शासन की मंशा के विपरीत यदि किसी जज ने फैसला देने का साहस किया है, तो उसे न्याय करने पर दंड दिया गया है। राजस्थान के एक जज दिनेश गुप्ता ने कानून के दायरे में रहकर राजस्थान सरकार के 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर करने वाला फैसला दिया। अदालत के इस फैसले से राजस्थान सरकार नाराज हो गई। रातों-रात जज महोदय का ट्रांसफर जयपुर से व्यावर कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जज साहब के फैसले को स्थगित कर देश के सबसे बड़े पूंजीपति को राहत देकर यह साबित कर दिया है, न्यायालय के सामने कौन है, उसको देखकर फैसले दिए जाएंगे।

राजस्थान के इस मामले में जज ने यह साबित किया। उसने संविधान और दस्तावेजों के आधार पर नियम के अनुसार बिना किसी पक्षपात के, सही निर्णय किया। इसके बाद भी उसे केवल इसलिए दंडित किया गया, कि न्यायालय के निर्णय से राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के हितों पर चोट पहुंची। देश के सबसे बड़ी पूंजीपति की कंपनी को जज साहब के फैसले से 1400 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा था। जज का। आधी रात को ट्रांसफर किए जाने के बाद न्यायापालिका और सरकार की एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। ऐसे साहसिक और ईमानदारी वाले फैसले अपवाद क्यों बनते जा रहे हैं? हर न्यायिक निर्णय के बाद जज की सुरक्षा, ट्रांसफर या भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं? क्या जज को सरकार और कॉर्पोरेट के हितों के विपरीत न्याय करने की कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर हां, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। आज देश में कई ऐसे मामले हैं,

जहां सालों तक फैसले नहीं आते, फैसले आते हैं तो वह सवालों के घेरे में होते हैं। आम आदमी को लगता है, ताकतवर के लिए न्यायालय में कानून अलग है, कमजोर के लिए अलग न्याय व्यवस्था है। राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट का यह फैसला इस धारणा को पुष्ट करता है। वर्तमान में न्यायापालिका की यह तस्वीर अब चिंताजनक है। असल सवाल यह है, जिस जज ने न्याय किया, उसे संरक्षण मिलना था। उसके विप रित वर्तमान व्यवस्था क्या जज को न्याय करने दे रही है? क्या राजनीतिक दबाव, मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया का शोर सत्य एवं न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बन रहा? अगर न्यायापालिका स्वतंत्र नहीं होगी, तो संविधान केवल कागज का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। जनता स्वयं निर्णय करने लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में न्यायापा लिका की भू मिका सरकार को संर क्षित करने की रही है। न्यायालयों में गरीबों को न्याय के स्थान पर ता रीख पर तारीख मिलती है।

बीसीसीआई ने टी-20 विश्वकप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की

टी20 विश्वकप में सूर्यकुमार करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी, शुभमन बाहर हुए, अक्षर होंगे उपकप्तान, ईशान किशन की वापसी

मुम्बई (एजेंसी)। अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली (बीसीसीआई) चयन समिति ने आगामी टी20 विश्वकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे पर इस टीम में उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया है। शुभमन अभी तक अपनी चोट से नहीं उबर पाये हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट में उपकप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को मिली है। अक्षर पहले भी उपकप्तानी संभाल चुके हैं। यही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी खेलेगी। टी20 विश्वकप की मेजबानी 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। शुभमन के अलावा युव विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं पिछले दो साल से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान को बैकअप के तौर पर रखा गया है। वह विकेटकीपर होने के साथ ही सलामी बल्लेबाज



भी हैं। ईशान ने झारखंड की कप्तान करती हुए मुस्ताक अल ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था

जिसका लाभ उन्हें मिला है। इसके अलावा फिनिशर रिकू सिंह की भी वापसी टीम में हुई है।

रिकू बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और आक्रामक बल्लेबाजी से मैच बदलने में माहिर हैं

हालांकि पिछले कुछ समय से वह लय में नहीं हैं। इसके बाद भी चयनकर्ताओं ने उनपर भरोसा दिखाया है। इसबार टीम में साल 2024 में विजयी टीम के सात खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। इसमें कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल हैं। रोहित, विराट और जडेजा ने संन्यास लिया है जबकि मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ और चहल को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

टीम इस प्रकार है

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुवे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वांशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर)

अगरकर ने बताया शुभमन, जितेश के बाहर होने का कारण



मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चयनसमिति ने आगामी टी20 विश्वकप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी। इस टीम में कुछ खिलाड़ियों को हाल में खराब प्रदर्शन के बाद भी जगह मिली है जबकि कुछ को अच्छे प्रदर्शन के बाद भी जगह नहीं मिली है। रिकू सिंह का टीम में चयन और अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाने पर भी सवाल उठे हैं। सबसे हैरानी की बात ईशान किशन का चयन है। वहीं लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उपकप्तान

शुभमन गिल को बाहर किये जाने पर कहा कि यह फैसला टीम संयोजन को ध्यान रखते हुए लिया गया है। टॉप में अगर आपके पास विकेट कीपर हो तो आप निचले क्रम तक अन्य बल्लेबाजों को अवसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगरकर ने शुभमन गिल की फॉर्म पर भी चिंता जताई। शुभमन का औसत इस साल अच्छा नहीं रहा है। वह टी20 में वह एक भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाये हैं। उनका बाहर होने का एक कारण फिट नहीं होना है। वहीं अगरकर ने माना है कि जितेश ने कोई गलती नहीं की पर उनके लिए टीम में जगह नहीं बन पायी क्योंकि सभी को शामिल नहीं किया जा सकता।

भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगा अंडर-19 एशिया कप फाइनल

दुबई (एजेंसी)। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच रविवार को यहां अंडर-19 एशिया कप फाइनल खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने ग्रुप ए में सभी मुकाबले जीते हैं। सेमीफाइनल में भारतीय टीम श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है। ऐसे में वह जीत की प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को भी ग्रुप चरण में 90 रनों से हराया है जिससे उसके हौसले बुलंद हैं।

भारतीय टीम की ओर से इस मैच में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुडू पर रहेंगी। वैभव ने यूएई के खिलाफ 95 गेंदों में 171 रन बनाए, जबकि अभिज्ञान कुडू ने मलेशिया के खिलाफ 125 गेंदों में नाबाद 209 रन बनाये थे। ऐसे में इस मैच में भी दोनों से धमाकेदार पारी की उम्मीद है। इनके अलावा आरोन जॉर्ज और विहान मल्लोत्रा ने भी काफी अच्छा खेला है।

वहीं गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्र ने पाकिस्तान और मलेशिया के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी कर अपने को साबित किया है। दूसरी ओर फरहान यूसुफ की कप्तानी वाली पाक टीम के पास काफी अच्छे तेज गेंदबाज हैं जिससे वह भारतीय टीम पर दबाव बनाना



चाहेगी। दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं।

टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्लोत्रा (उपकप्तान), वेदात त्रिवेदी, अभिज्ञान कुडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन गुपक, डी. दीपेश, हेनल

पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज।
पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास, मोहम्मद हुजैफा।

बुमराह की फिटनेस के लिए उन्हें आराम दिया जाना जरूरी : रॉबिन उथप्पा



लखनऊ। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बीच-बीच में आराम दिया जाना बेहद जरूरी है। उथप्पा के अनुसार बुमराह का एक्शन काफी कठिन है। इसके साथ ही उनकी गति भी काफी तेज है जिससे उनके शरीर पर काफी दबाव आता है और चोटिल होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में उनका कार्यभार प्रबंधन का ध्यान देना जरूरी है। बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमक की कमाना संभालते हैं और अगले साल होने वाले टी20 विश्वकप को देखते हुए उनका फिट बने रहना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में बुमराह को आराम दिया गया था और उन्होंने पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी की। उथप्पा ने कहा, 'वह एक शानदार मैच विजेता खिलाड़ी है पर उनके कार्यभार का प्रबंध करना बेहद जरूरी है। तेज गेंदबाजी क्रिकेट का सबसे मुश्किल कौशल है और बुमराह इसे बेहद तेज गति से और चुनौतीपूर्ण एक्शन के साथ करते हैं। उन्होंने कहा, 'आप उनको पूरी तरह से फिट बनाए रखना चाहते हैं पर साथ ही आप यह भी चाहते हैं कि वह पर्याप्त क्रिकेट खेलें। इसके लिए काफी सूझबूझ से उनका कार्यभार प्रबंधन करना होगा जिससे वह लय में भी बने रहे और उनके शरीर पर जरूरत से ज्यादा बोझ भी न पड़े। उनकी प्रतिभा और कौशल पर किसी को भी संदेह नहीं है।

मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया है... टी20 विश्व कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने फैस से किया बड़ा वादा

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने हालिया खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले फॉर्म में वापसी का भरोसा जताया। 2025 में, यादव टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 21 मैचों में 13.62 के खराब औसत से 218 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है।

यहां आगामी टी20 विश्व कप में 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल को फिटनेस और फॉर्म संबंधी चिंताओं के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है, और अक्षर पटेल उप-कप्तान के रूप में

वापसी कर रहे हैं। शनिवार को बीसीसीआई के मुख्यालय में कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की उपस्थिति में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम की घोषणा की।

यादव ने पत्रकारों से कहा कि मुझे पता है कि क्या करना है, कहीं गड़बड़ हो रही है। मेरे पास इस पर काम करने के लिए कुछ समय है। यह बस एक छोटी सी अदृश्य बाधा है जिसे मैं निश्चित रूप से पार कर लूंगा। गिल को टीम से बाहर किए जाने पर व्यापक बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया है। कप्तान यादव ने इस फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि चयन खिलाड़ियों की भूमिका और संरचना को ध्यान में रखकर किया गया है, न कि उनके अल्पकालिक

प्रदर्शन को।

यादव ने कहा कि यह प्रदर्शन की बात नहीं है, यह तालमेल की बात है। हम शीर्ष क्रम में एक विकेटकीपर चाहते थे। हम गिल की गुणवत्ता को जानते हैं। हम रिकू सिंह और वांशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को भी अंतिम खेर पर चाहते थे। यादव के लिए, घरेलू विश्व कप में टीम की कप्तानी करना अवसर और जिम्मेदारी दोनों हैं। यादव ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक अच्छी जिम्मेदारी है... अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलना एक अच्छी चुनौती होगी। भारत को ग्रुप 'ए' में नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रखा गया है और भारत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।



श्रीलंका ने असलंका की जगह शनाका को नया कप्तान बनाया



कोलंबे (एजेंसी)। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टी20 विश्व कप से पहले कप्तानी से चरित असलंका को हटा दिया है। वहीं दासुन शनाका को नया कप्तान बनाया गया है। चयन समिति के प्रमुख प्रमोदा विक्रमसिंघा ने कहा कि शनाका को लंबा अनुभव है। उन्होंने तीन विश्वकप खेले हैं। वहीं असलंका का फार्म पिछले काफी समय से अच्छा नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि असलंका पिछले महीने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे पर जाने से इंकार कर दिया था, इसी कारण उन्हें कप्तानी से हटाया गया है।

विक्रमसिंघे के अनुसार, असलंका की खराब बल्लेबाजी फॉर्म और कप्तानी के बढ़ते बोझ को देखते हुए उनकी जगह शनाका को कप्तानी दी गयी है। असलंका टीम में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में बने रहेंगे। बोर्ड चाहता है कि असलंका बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी करें। विक्रमसिंघा ने कहा, 'नये कप्तान शनाका ऑलराउंडर

की भूमिका निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि असलंका बल्लेबाजी में अपनी लय हासिल कर लेंगे। मुख्य कोच सनत जयसूर्या से सलाह के बाद हमने तय किया कि बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है इसलिए टीम में अधिक बदलाव नहीं किये हैं। '

वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की चार साल बाद टीम में वापसी हुई है।

श्रीलंका प्रारंभिक टीम : दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल पररा, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानांगे, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अराचिगे, वांनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालाम्गे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, एशान मलिंगा, दुर्भंता चामेरा, प्रमोद मदुशान, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीष तीक्ष्णा, दुशान हेमंता, विजयकांत वियासकांत, टूवीन मैथ्यू।

हार्दिक ने युवराज का एक रिकार्ड तोड़ा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत में अहम भूमिका निभाई है। इस मैच में तेजी से अर्धशतक लगाने के साथ ही एक विकेट लेकर पंड्या ने पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का का एक रिकार्ड तोड़ दिया है। टी20 अंतरराष्ट्रीय टी20 में यह चौथा मौका था जब पांड्या ने अर्धशतक लगाने के साथ ही 1 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा। युवराज ने टी20 में तीन बार अर्धशतक लगाने के साथ ही 1 या उससे अधिक विकेट लिए थे। विराट कोहली और शिवम दुबे भी 2-2 बार यह कारनामा किया है। हार्दिक ने केवल 16 गेंदों में ही तेजी अपने 50 रन पूरे किये। भारत की तरफ से टी20 में यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। पांड्या ने 25 गेंदों पर ही 5 छक्के और 5 चौकों लगाकर 63 रन बनाये। इससे भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन बनाये। हार्दिक ने इसके बाद गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिया।



वार्षिक खेल महोत्सव 'सिटियस -2025' का हुआ आयोजन

क्रांति समय
www.krantisamay.com & www.epaper.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विद्या विहार स्कूल के वार्षिक खेल महोत्सव 'सिटियस-2025' का आयोजन 6 से 19 दिसंबर 2025 के बीच स्कूल परिसर एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस खेल महोत्सव में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक के 3,000 छात्रों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सरावगी एवं अन्य गणमान्य पदाधिकारियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर विजेताओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया। ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ यह उत्सव 20 दिसंबर को ध्वज उतारने की रस्म और राष्ट्रगान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य छात्रों में एकता एवं खेल भावना का संचार करना था।

अग्रवाल प्रीमियम लीग-17 प्लेयर ऑक्शन का हुआ आयोजन
क्रांति समय
www.krantisamay.com & www.epaper.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा द्वारा अग्रवाल प्रीमियर लीग (एपीएल) सीजन 17 का आयोजन 16 जनवरी से बी.जे. पटेल ग्राउंड, अलथायन में किया जाएगा। इसके किए शनिवार को सिटीलाइट स्थित महाराजा अग्रसेन चैलेंस में प्लेयर ऑक्शन का आयोजन किया गया। ऑक्शन में कुल 12 टीमों ने भाग लिया, जहाँ टीम संयोजकों ने अपनी रणनीतिक के तहत बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करते हुए अपनी-अपनी टीमों की मजबूती बढ़ाई। ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों के चयन को लेकर खासा उत्साह और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस अवसर पर अग्रवाल विकास ट्रस्ट के मनीष अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, निशित बेडिया, प्रशांत अग्रवाल, युवा शाखा अध्यक्ष अंकित झुनझुनावाला सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने आगामी टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।



संक्षिप्त समाचार

अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप

झकाबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान में शुक्रवार को 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही, जिससे जमीन के तेज हिलने और आफ्टरशॉक की आशंका बनी हुई है। एनसीएस ने बताया कि भूकंप 19 दिसंबर 2025 को रात 12:14 बजे (आईएसटी) आया, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में 36.76 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.08 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। विशेषज्ञों के मुताबिक उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंगें सतह तक कम दूरी तय करती हैं और नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी अफगानिस्तान में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था। अफगानिस्तान हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। नवंबर में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में कई लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट के स्थानीय संगठन के प्रवक्ता को किया गिरफ्तार

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट के स्थानीय संगठन 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी)' के प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही आतंकी है, जिसे अमेरिका ने 2021 में आतंकवादी घोषित किया था। यह जानकारी गुरुवार को सरकारी मीडिया ने दी। विशेषकों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से इस उग्रवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है, जो हाल के वर्षों में क्षेत्र में फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरफ्तारी मई महीने में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुल्तान अजीज अजाम, जो आईएसकेपी का प्रवक्ता है, को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। अजीज अजाम मूल रूप से अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत का रहने वाला है। पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

यरुशलम में अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स की पुलिस से झड़प, कई घायल

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइल के यरुशलम के अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हरेदीम) यहूदी बहुल इलाके में गुरुवार को उस वक़्त हिंसक झड़प हो गई, जब इस्राइली अधिकारियों ने एक सामान्य पार्किंग चालान काटने की कोशिश की। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार एक पुलिस इस्पेक्टर द्वारा पार्किंग टिकट जारी करने की कोशिश के दौरान उस पर हिंसा और धमकियां दी गईं। पुलिस ने शुरू में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन इसके बाद सैकड़ों अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स प्रदर्शनकारी मौक़े पर पहुंच गए और संदिग्ध को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर पत्थर व अंडे फेंके गए।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई गुरुवार को अदालत में पेश न होने के कारण की गई। इस्लामाबाद की एक वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में राज्य संस्थानों के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक आरोप लगाने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा मामला चल रहा है। सुनवाई के दौरान न तो मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी और न ही उनके वकील अदालत में उपस्थित हुए। न्यायाधीश अब्बास शाह ने गैर-हाजिरी को गंभीर मानते हुए गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह मामला राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि अदालत ने 11 दिसंबर को पहले ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे।

एफबीआई के उप निदेशक डैन बॉगिनो जनवरी में देंगे इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के उप निदेशक डैन बॉगिनो ने कहा कि वह अगले महीने इस्तीफा दे देंगे। उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिकी निवेशक एवं यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की फाइलों को लेकर न्याय मंत्रालय के साथ उनका टकराव हुआ। बॉगिनो के इस्तीफे की पहले से ही उम्मीद थी और उनका इस्तीफा ट्रंप प्रशासन के सबसे वरिष्ठ इस्तीफाओं में से एक होगा।

यूके की अदालत में एनआरआई महिला की जंग, बीमारी के बावजूद लड़ रही बराबरी के हक की लड़ाई

लंदन, एजेंसी। यूके की एक अदालत में एक एनआरआई महिला पिछले छह साल से अपने कार्यस्थल पर ईसाफ और बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रही है। यह मामला सिर्फ एक नौकरी से जुड़ा विवाद नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज है, जो गंभीर बीमारी के बावजूद काम करती हैं और कार्रपोरेट सिस्टम की कठोर नीतियों का शिकार होती हैं। पश्चिम बंगाल की संजु पाल की यह लड़ाई अब हाईकोर्ट अपील ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुकी है।

लंदन में चल रहे इस मामले में संजु पाल ने यूके के समानता कानून 2010 और रोजगार अधिकार अधिनियम 1996 के तहत अपने अधिकारों की मांग की है। संजु पाल एंडोमेंट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी के कारण उन्हें कार्यस्थल पर भेदभाव झेलना पड़ा और अप या आउट जैसी कार्रपोरेट नीति के तहत उन्हें नौकरी

से बाहर कर दिया गया। **बीमारी और भेदभाव का मुद्दा :** एंडोमेंट्रियोसिस एक पुरानी बीमारी है, जिससे यूके में करीब 15 लाख महिलाएं प्रभावित बताई जाती हैं। इस बीमारी में तेज दर्द और शारीरिक कमजोरी होती है। संजु पाल का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने से पहले वह इसी बीमारी से जूझ रही थीं। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने पहले यह मानने से इनकार कर दिया कि यह बीमारी कानूनी रूप से विकलांगता की श्रेणी में आती है। अब इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

नौकरी से निकाले जाने का विवाद : यह मामला वर्ष 2019 का है, जब संजु पाल को एक कंसल्टिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर पद पर पदोन्नति नहीं मिलने के बाद कथित खराब प्रदर्शन के आधार पर नौकरी से हटा दिया गया। कंपनी की नीति के अनुसार यदि कोई कर्मचारी तय समय में अगली पोस्ट के



लिए तैयार नहीं माना जाता, तो उसे बाहर किया जा सकता है। संजु पाल का तर्क है कि कानून मौजूद पद पर कामकाज के आधार

पर ही आकलन की अनुमति देता है, न कि भविष्य की भूमिका के आधार पर। **कोर्ट की सुनवाई और अपील :** रोजगार ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2022 में संजु पाल के पक्ष में आंशिक फैसला सुनाया और उन्हें अनुचित बर्खास्तगी के लिए मुआवजा दिया। हालांकि, विकलांगता से जुड़े दावे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट अपील की अनुमति मिली। दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आने वाले हफ्तों में फैसला आने की उम्मीद है। संजु पाल ने इस लड़ाई के लिए ऑनलाइन अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी जुटाई।

व्यापक असर और उम्मीद : संजु पाल का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है, तो इससे कंसल्टिंग सेक्टर और दूसरे कॉरपोरेट क्षेत्रों में काम करने वाली बीमार कार्यस्थल पर गैरकानूनी और अमानवीय नीतियां खत्म हों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की 68 नई तस्वीरें जारी: बिल गेट्स महिलाओं के साथ दिखे

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज किया है। इनमें से दो तस्वीरों में अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या अलग-अलग। इसके अलावा गुगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन, फिल्ममेकर वुडी एलन, फिलॉस्फर नोम चॉमस्की और ट्रम्प के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोग नजर आ रहे हैं।

यहां यह साफ कर दें कि इन तस्वीरों का यह मतलब नहीं है कि ये लोग किसी गलत काम में शामिल थे। इसकी जानकारी एपस्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद ही आएगी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट कल इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी सभी फाइलें रिलीज करने वाला है। इससे पहले 12 दिसंबर को 19 तस्वीरें जारी की गई थीं, जिनमें भी बिल गेट्स नजर आए थे।

तस्वीरों में महिला के शरीर पर मैसेज लिखा दिखा : नई तस्वीरों में महिला के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे गए मैसेज दिखाई दे रहे हैं। **स्क्रिण** की रिपोर्ट के मुताबिक यह मशहूर किताब लोलिता से लिए गए मैसेज हैं। एक तस्वीर में इस किताब की कॉपी भी पीछे नजर आती है।

‘लोलिता’ एक विवादित उपन्यास है। इसमें एक नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी लिखी है। इसी वजह



से महिला के शरीर पर इस किताब से जुड़े मैसेज को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसे संवेदनशील मामला माना जा रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये सभी मैसेज एक ही महिला के शरीर पर लिखे गए हैं या अलग-अलग महिलाओं पर। तस्वीरें किस मकसद से ली गईं, इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

वॉट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट भी जारी : जारी की गई तस्वीरों में एक स्क्रीनशॉट भी शामिल है, जिसमें किसी अनजान भेजने वाले को वॉट्सएप चैट दिखती है। इन मैसेज में से एक में ‘फ्रेंड स्काउट’ का जिक्र है और कहा गया है कि उसने ‘हर लड़की

के बदले 1000 डॉलर’ मांगे हैं। इसे भेजने वाले का अगला मैसेज है, ‘मैं अब तुम्हें लड़कियां भेजुंगा’। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये मैसेज किसके हैं, किसे भेजे गए और ‘जे’ किस व्यक्ति के लिए लिखा गया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट भी दिखे, अखबार ने बयान जारी किया : न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स भी एक तस्वीर में दिखे हैं। ऐसा लगता है कि डेविड ब्रूक्स किसी लंच या डिनर कार्यक्रम में शामिल थे। वे गुगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम 2011 में हुआ था, यानी उस समय के तीन साल

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश

नॉर्थ कैरोलिना, एजेंसी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हो गया है। यहां एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पूर्व एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके पूरे परिवार समेत सात लोगों की मौत हो गई। यह हवाई अड्डा एनएससीएआर टीमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई। यह विमान चार्लोट से करीब 45 मील उत्तर में स्थित स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी सात लोग हादसे का शिकार हुए। फ्लाइट रिकॉर्ड से पता चल है कि यह प्लेन रिटायर्ड एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सेसना



सी550 में छह लोग सवार थे, जो चार्लोट से लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) उत्तर में स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

नॉर्थ कैरोलिना स्टेट हाइवे पेट्रोल ने पुष्टि की कि विमान में सवार लोगों में 55 वर्षीय ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टीना, 14

वर्षीय बेटी एम्मा और 5 वर्षीय बेटा राइडर शामिल थे। इनके अलावा डेनिस डउन, उनके बेटे जैक डउन और क्रैग वाइस्वर्थ भी विमान में मौजूद थे।

क्रैश के वक्त हल्की बारिश और बादल थे : इरेडेल काउंटी शेरिफ डैरेन कैम्बेल ने कहा, ‘मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इसमें लोगों

पाकिस्तान में आईएस-के प्रवक्ता सुल्तान अजीज अजम हुए गिरफ्तार, यूएनएससी की रिपोर्ट से मिली जानकारी

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सीपी गई एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस वर्ष इस्लामिक स्टेट-खुरासान (आईएस-के) के प्रवक्ता सुल्तान अजीज अजम को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 16वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने कुछ हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों की हैं, जैसे कि इस मई में अजम की गिरफ्तारी हुई है। इस कारण क्षेत्र में आईएस-के की सक्रियता कम हो गई है। बता दें कि आईएस-के इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत का संक्षिप्त रूप है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। सरकारी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और पीटीवी न्यूज ने बताया कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास एक अभियान के दौरान अजम को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, अल-अजैम फाउंडेशन जैसे आईएस-के के प्रचार तंत्र को भारी झटका लगा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के की वजह से आईएसके की क्षमता में कमी आई- संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘कुल मिलाकर, आतंकवाद विरोधी अभियानों के की वजह से आईएसके की क्षमता में कमी आई है। आईएसके के प्रमुख कमांडरों और विचारकों को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएसके लड़ाकों की संख्या में भी कमी आई है। कई नियोजित हमलों को नाकाम कर दिया गया है।’



आत्महत्या की है। जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के साथ ही हाल ही में बुकलिन में एमआईटी के प्रोफेसर की भी हत्या की थी। हालांकि दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इस बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया।

ब्राउन यूनिवर्सिटी को गोलीबारी में दो लोगों की मौत हुई : बीते शनिवार को ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हुई थी और नौ अन्य लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच गुरुवार को तब बदल गई, जब अधिकारियों ने कहा कि वे ब्राउन में हुई सामूहिक गोलीबारी और बोस्टन के पास दो दिन बाद हुए हमले के बीच संबंध की जांच कर रहे हैं, जिसमें मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नूतन एफजी लोरेडो की मौत हो गई थी। हालांकि एफबीआई ने कहा था कि उसे दोनों मामलों के बीच के लिंक की कोई जानकारी नहीं है। हमलावर की पहचान अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोलीबारी करने वाला संदिग्ध ब्राउन यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र था और करीब 25 साल पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका था।

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश

नॉर्थ कैरोलिना, एजेंसी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हो गया है। यहां एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पूर्व एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके पूरे परिवार समेत सात लोगों की मौत हो गई। यह हवाई अड्डा एनएससीएआर टीमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई। यह विमान चार्लोट से करीब 45 मील उत्तर में स्थित स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी सात लोग हादसे का शिकार हुए। फ्लाइट रिकॉर्ड से पता चल है कि यह प्लेन रिटायर्ड एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सेसना

सी550 में छह लोग सवार थे, जो चार्लोट से लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) उत्तर में स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश

नॉर्थ कैरोलिना, एजेंसी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हो गया है। यहां एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पूर्व एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके पूरे परिवार समेत सात लोगों की मौत हो गई। यह हवाई अड्डा एनएससीएआर टीमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई। यह विमान चार्लोट से करीब 45 मील उत्तर में स्थित स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी सात लोग हादसे का शिकार हुए। फ्लाइट रिकॉर्ड से पता चल है कि यह प्लेन रिटायर्ड एनएससीएआर ड्राइवर ग्रेग बिफल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सेसना

सी550 में छह लोग सवार थे, जो चार्लोट से लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) उत्तर में स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया।

नॉर्थ कैरोलिना स्टेट हाइवे पेट्रोल ने पुष्टि की कि विमान में सवार लोगों में 55 वर्षीय ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टीना, 14 वर्षीय बेटी एम्मा और 5 वर्षीय बेटा राइडर शामिल थे। इनके अलावा डेनिस डउन, उनके बेटे जैक डउन और क्रैग वाइस्वर्थ भी विमान में मौजूद थे।

क्रैश के वक्त हल्की बारिश और बादल थे : इरेडेल काउंटी शेरिफ डैरेन कैम्बेल ने कहा, ‘मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इसमें लोगों

मेसी इवेंट विवाद :कोलकाता पुलिस ने आयोजक सतद्रु दत्ता के घर की तलाशी ली, 100 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच तेज

कोलकाता (एजेंसी)। साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित लियोनेल मेसी इवेंट में मचे बवाल के मामले में कोलकाता पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने इस विवादित इवेंट के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता के आवास पर छापेमारी कर आलीशान सुविधाओं का खुलासा किया। पुलिस की जांच में दत्ता के तीन मंजिला मकान में स्विमिंग पूल, टैरेस पर फुटबॉल ग्राउंड और एक बड़ा कार्यालय पाया गया। यह तलाशी विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई, जो इवेंट से जुड़े धुंधलेपन और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह एक ‘प्रक्रियात्मक तलाशी’ थी, जिसके दौरान घर में मौजूद दस्तावेजों और विभिन्न समझौतों की जांच की गई। हालांकि, इस छापेमारी में कोई सामान जब्त नहीं किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई रिश्वत रिशत सतद्रु दत्ता के आवास पर की गई। इस दौरान बिधाननगर पुलिस की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने घर के हर कमरे की जांच की और वहां मौजूद केयरटेकर से पूछताछ की। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच केवल भेड़ नियंत्रण में हुई चूक तक सीमित नहीं है, बल्कि अब बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका भी सामने आ रही है।

एसआईआर : तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा , गुजरात में 73.73 लाख नाम काटे

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। एसआईआर से पहले राज्य में वोटर्स की संख्या 6.41 करोड़ थी। अब घटकर 5.43 करोड़ हो गई है। राज्य में अब 2.66 करोड़ पुरुष, 2.77 करोड़ महिलाएं और 7, 19।1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चेन्नई में सबसे ज्यादा 14.25 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं। पहले यहां 40.04 लाख वोटर्स थे अब 25.79 लाख रह गए हैं। कोयंबटूर में 65 लाख, डिंडीगुल में 23 लाख नाम काटे गए हैं। वहीं गुजरात की जारी नई एसआईआर लिस्ट में 73.73 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कम हुए हैं। राज्य में पहले 5.08 करोड़ से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब घटकर 4.34 करोड़ रह गए हैं। अगर यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तब वह 18 जनवरी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इसके अलावा बंगाल की नई मतदाता सूची जारी की गई है। कुल 58.20 लाख नाम काटे गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। राजस्थान में भी 44 लाख नाम काटे गए हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.04 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

पुरुष बंदियों के बाद अब मध्यप्रदेश में महिला कैदियों के लिए खुली जेल

-अब तक महाराष्ट्र और राजस्थान में ही ऐसी व्यवस्था

भोपाल (एजेंसी)। महिला कैदियों के लिए जेल विभाग ने अपने मैनुअल बदलने की तैयारी की है। अब तक प्रदेश में सिर्फ पुरुष बंदियों के लिए खुली जेल थी, लेकिन मोहन सरकार की मुहर के बाद मध्यप्रदेश तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा, जहां महिला कैदियों को खुली जेल में रखा जाएगा। अब तक महाराष्ट्र और राजस्थान में ही ऐसा है। जेल विभाग के संसोधन के बाद प्रदेश की जेलों में बंद 1600 महिला कैदी भी सजा अविध में खुली हवा में सांस ले पाएंगी। जेल विभाग की नई प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन महिला कैदियों को ही मिलेगा, जिन्होंने या कुल सजा की दो तिहाई अवधि पूरी की है या जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। खुली जेल में अच्छे व्यवहार, कम खतरनाक और सजा का बड़ा हिस्सा काट चुके कैदियों को यहां रखा जाता है। कैदी वन बीघर के जैसे कारभो में रहते हैं। जहां वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी रह सकते हैं। महिलाओं को खुली जेल में रातने की पास्ता देने की योजना बनाई है। शासन को संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही सुविधा मिलेगी। प्रदेश में अभी भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में खुली जेल संचालित हैं। इनमें फिलहाल केवल पुरुष कैदियों को ही रखा जाता है।

पंजाब के किसानों ने प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर अपना फैसला बदला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के किसानों ने प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर अपना फैसला बदला है। 20 दिसंबर को होने वाला विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के आधासनों के बाद स्थगित किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह भंडार ने बताया कि गुरुवार शाम को मान सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों को आधासन दिया गया। कि बिजली संधिषण विधेयक पंजाब में लागू नहीं होगा। मान सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के संबंध में भी सकारात्मक आधासन देकर कहा कि इस्तरफ मीटर राज्य में नहीं लगाए जाएंगे। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय मान सरकार के आधासनो को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि, उन्होंने दो टूक कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया है, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। इस बीच, किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए किसान प्रतिनिधियों और पंजाब सरकार के बीच 22 दिसंबर को एक और बैठक निर्धारित की गई है। किसान मजदूर मोर्चा (कैएमएम) के आह्वान पर और दशमेश किसान मजदूर युनियन के समर्थन से आयोजित यह विरोध प्रदर्शन पंजाब भर में 18 और 19 दिसंबर को जिला आयुक्त कार्यालयों के बाहर चल रहे दो दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा था।

दिल्ली में वाहन लेकर प्रवेश करने वालों पर लगा 20–20 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में सर्दियों के शुरू होते ही वायु प्रदूषण फिर से चिंता का कारण बन गया है। राजधानी की हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) लगातार गंभीर और अति-गंभीर स्तर पर बनी हुई है, जिससे बाहर सांस लेना मुश्किल हो गया है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और सांस की बीमारी से ग्रसित लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें वाहनों पर सख्त निगरानी भी शामिल है। पहले दिन ही 10 वाहनों पर 20–20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें वापस भेजा गया।

तीन माह में तीसरे तालिबानी मंत्री का दिल्ली दौरा... पाकिस्तान को लग गई मिर्ची

नई दिल्ली (एजेंसी)। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली का भारत दौरा कई मायनों में अहम है। बता दें कि बीते तीन माह में भारत आने वाले वे तीसरे तालिबान मंत्री हैं। इससे पहले अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी और उद्योग व वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भारत आ चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जलाली का स्वागत विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने किया।

यात्रा के दौरान जलाली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को दीर्घकालिक आधार पर दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का भरपौरा दिया। भारत ने कैसर वैकसीन सहित कई जीवनरक्षक टीकों का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी किया। बता दें कि भारत पहले ही अफगानिस्तान को 63,734 डोज इन्फ्लुएंजा और मेनिन्जाइटिस वैकसीन तथा 73 टन आवश्यक दवाइयां भेज चुका है। आने वाले समय में 128 स्लाइस सीटी स्कैनर सहित बड़ा मेडिकल कंशुइनमेंट भेजने की तैयारी है। यह दौरा तब हो रहा है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और सीमा बंद होने से अफगान व्यापार बुरी तरह प्रभावित



हुआ है।

भारत ने बिना शोर मचाए, बिना मान्यता दिए, मानवीय सहायता से अफगानिस्तान में अपनी जगह फिर बना ली है। ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान को जिस अंतरराष्ट्रीय अलगाव में धकेल दिया गया था, वहां भारत अकेला बड़ा देश है जिसने 'लोगों के साथ खड़े

रहने' की नीति लागू की। अस्पताल, दवाइयां, वैकसीन, मेडिकल वीजा, भारत ने कभी अफगान जनता से नाता नहीं तोड़ा। यही वजह है कि आज तालिबान के मंत्री एक के बाद एक दिल्ली का रुख कर रहे हैं।

पाकिस्तान की पेशानी इसी बात है। दशकों तक अफगानिस्तान को ारणीतिक गहराई-समझने वाला इस्लामाबाद आज खुद हाशिये पर

खड़ा है। सीमा बंद कर व्यापार रोकना, अफगान शरणार्थियों पर दबाव, और तालिबान को आंख दिखाने की नीति उलटी पड़ गई। नतीजा हुआ कि काबुल ने दिल्ली की आरे देखना शुरू कर दिया। वह अफगानिस्तान में न बंदूक भेज रहा है, न फौज। वह भेज रहा है दवा, डॉक्टर, मशीन और भरपौरा। यह सॉफ्ट पावर दरअसल हार्ड पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा असरदार दिख रहा है। स्वास्थ्य सहयोग के जरिये भारत अफगान समाज की जड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और यही किसी भी दीर्घकालिक प्रभाव की बुनियाद होती है। इससे अफगानिस्तान में भारत विरोधी तत्वों के लिए ज़मीन सिकुड़ती है। साथ ही वहां पाकिस्तान का एकाधिकार टूटता है। इसके अलावा, मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के रास्ते खुलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में वह कर दिखाया है जो पाकिस्तान बंदूक और दबाव से नहीं कर सका, यानि विश्वास के जरिये भारत ने वहां के नए शासकों का दिल जीत लिया। खनन, ऊर्जा, हाइड्रो प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य, हर सेक्टर में भारत की वापसी के संकेत साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तान इस सबसे चिढ़ कर इसलिए बयान दे रहा है क्योंकि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है।

बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अशोक गहलोत ने जताई चिंता, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग

जयपुर (एजेंसी)। कांग्रेस के बाहरी ताकतों को बल मिल रहा है, वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालिया हिंसा और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा, कि बांग्लादेश में और वहां हिंदू भड़की हिंसा और वहां हिंदू



कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाए और बांग्लादेश सरकार से स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय शांति और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए भारत का स्पष्ट और

सशक्त रुख जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमले अंतर्र चिंताजनक और निंदनीय हैं। विद्रोह के प्रमुख नेताओं में शामिल शरीफ उस्मान हादी की हालिया मौत के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। इन प्रदर्शनों के दौरान कई स्थानों पर हिंसा की घटनाएं सामने आईं, जिससे पूरे देश में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इन घटनाओं के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों की निशाना बनाए जाने आरोप लगाया कि केंद्र की चुप्पी से बांग्लादेश में सक्रिय भारत विरोधी और

पुलिस से धक्का-मुक्की मामले में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा पर चलेगा मुकदमा, डिस्टार्ज याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक मार्ग बाधित करने के मामले में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राजन एवेन्यु कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अध्वनी पंवार की मुदख्त करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

यह मामला 29 जुलाई 2024 को जंतर-मंतर पर हुए उस प्रदर्शन से जुड़ा है, जो कांग्रेस महिला इकाई द्वारा महिला आरक्षण के समर्थन में आयोजित किया गया था। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा के बारे में पहले ही अवगत करा दिया था और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया था। इसके बावजूद अलका लांबा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर घेराव करने की कोशिश की, बैरिकेड्स पर किए और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध किया। सुनवाई के



किया गया है, जिससे आरोप कमजोर होते हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को आरोप तय करने के स्तर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत विचार मुकदमे के दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने अलका लांबा की डिस्टार्ज याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए यात्रा कार्यक्रम नहीं मांग सकता प्राधिकरण : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के संवैधानिक ढांचे में स्वतंत्रता राज्य का उपहार नहीं, बल्कि उसका पहला दायित्व है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट नवीनीकरण के चरण में पासपोर्ट प्राधिकरण किसी व्यक्ति से भविष्य की यात्रा योजनाओं या वीजा की अनुसूची की मांग नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण की भूमिका सीमित है। उसका दायित्व केवल यह जांचना है कि लंबित आपराधिक कार्यवाही के बावजूद संबंधित

आपराधिक अदालत ने अपनी निगरानी में व्यक्ति को यात्रा की अनुमति देने का विकल्प खुला रखा है या नहीं। अदालत ने कहा कि नवीनीकरण के समय संभावित या अभी अस्तित्व में ही न होने वाली यात्राओं का विवरण मांगना तर्कसंगत नहीं है। पीठ ने कहा, कि हमारे संवैधानिक ढांचे में स्वतंत्रता राज्य का उपहार नहीं बल्कि उसका पहला दायित्व है। कानून के अधीन रहते हुए किसी नागरिक को आवागमन, यात्रा, आजीविका और अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को

प्रशासनिक औपचारिकताओं के नाम पर अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता। यह आदेश महेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिया गया। अग्रवाल झारखंड के रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) के तहत कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जमानत की शर्तों के तहत उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा किया हुआ, लेकिन उनका पासपोर्ट व्ष 2023 में समाप्त हो गया था। अग्रवाल ने पासपोर्ट के नवीनीकरण

की अनुमति मांगी थी, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता को पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश देने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया और पासपोर्ट प्राधिकरण को उनका पासपोर्ट नवीनीकृत करने का निर्देश दिया। अदालत ने दोहराया कि नवीनीकरण के स्तर पर वीजा या भविष्य की यात्रा योजनाओं की मांग करना कानूनन उचित नहीं है।

पासपोर्ट प्राधिकरण को उनका पासपोर्ट नवीनीकृत करने का निर्देश दिया। अदालत ने दोहराया कि नवीनीकरण के स्तर पर वीजा या भविष्य की यात्रा योजनाओं की मांग करना कानूनन उचित नहीं है।



देश में पिछले तीन वर्षों में बसों में आग लगने की 45 घटनाएं... कुल 64 लोगों की मौत



नई दिल्ली। देश में पिछले तीन वर्षों में चलती बसों में आग लगने की 45 घटनाएं हुई हैं। इन हदसों में कुल 64 लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्यसभा में दी। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सिडेंट रिपोर्ट (ईडीएआर) पोर्टल के आंकड़ों में 2023, 2024 और 2025 (10 दिसंबर तक) की घटनाएं शामिल हैं। 2023 में बस में आग की 11 घटनाएं हुईं, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई। 2024 में 20 घटनाओं में 31 लोग की जान गईं। 2025 में अब तक 14 घटनाओं में 32 मौतें दर्ज की गई हैं। इन तीन वर्षों में कुल 145 लोग घायल भी हुए हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 24 अक्टूबर 2025 को हुई बस दुर्घटना, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी, इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि बसों में आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को अपडेट किया जा रहा है। एआईएस-119 मानकों में संशोधन किया है, ताकि हर बस में फायर एक्सटिंग्विशर और अतिरिक्त आपातकालीन निकास होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा, एयुल सिरटम और इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित सुरक्षा नियमों को कड़ा कर दिया गया है। सरकार राज्यों को लगातार निर्देश दे रही है ताकि पुराने वाहनों में भी सुरक्षा उपकरण लगाए जा सकें और हदसों की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए।

कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा आरोप, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर और एक आत्मा -विदेशी दौरे पर भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विश्व के नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं। प्रेसवार्ता में बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करना, भारत विरोधी ताकतों से मिलना, ये सभी काम राहुल गांधी कर रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ही संसदीय सत्रों के दौरान विदेश यात्रा

करते हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने हाल ही में जर्मनी की यात्रा से दिया। भाटिया ने कहा कि विश्व के नेता, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सत्र के दौरान संसद में उपस्थित रहना है, लेकिन वे विदेश चले गए, जहां उन्होंने हटी स्कूल में जाकर प्रोफेसर डॉ. कॉर्नेलिया वोल से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस (एक निवेशक और पोपकारी व्यक्ति, जिन पर हमेशा दक्षिणपंथी लोग निशाना साधते हैं) के बीच संबंध हैं। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का हवाला देकर कहा कि इन संस्थाओं का भारत विरोधी गतिविधियों

से संबंध है। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर, एक आत्मा (दो जिस्म, एक जान) की तरह हैं, और अलग एक और सबूत सामने आया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। भाटिया ने पूछा कि वे विदेश जाते हैं और भारत के दुश्मनों, भारत से इथ्या करने वालों और हमलों अखंडता पर हमला करने वालों से मिलते-जुलते हैं। यह किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा है, जहां भारत का विश्व नेता ऐसी ताकतों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है?



नकली कफ सिरप विवाद में एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे अखिलेश और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाटक

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप (कोडीन आधारित) के अवैध कारोबार को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा सरकार (उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाटक) के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ गई है। जहां सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार और भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाकर घेराबंदी की है। उन्होंने दावा किया कि हर विभाग में लूट मची है और सरकार बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश ने लिखा, ‘‘ नशाखोरी की जांच के लिए ‘सिरप टॉस्क फोर्स’ मतलब एसटीएफ के साथ-साथ जीटीएफ भी बना दीजिएजबाकी जनता समझदार है। भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां वगैरें उड़ी हुई हैं? कोडीन कफ सिरप की सच्चाई ये जानते हैं तभी खुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खासी भी आ गयी। हालांकि, यादव ने ‘जीटीएफ का मतलब नहीं समझाया। नकली कफ सिरप के कारोबारियों पर सरकार का बुलबुलार खामोश है। वाराणसी से शुरू होकर यह अवैध कारोबार जिले-जिले होते हुए अन्य प्रदेशों और विदेश तक पहुंच गया। वहीं उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाटक ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देकर उन्ही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाटक ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें अखिलेश यादव कथित तौर पर इस रेकेट के मुख्य आरोपियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो सपा के शासनकाल में फले-फूलें और आज माफिया राज के प्रतीक हैं। पाटक ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के इन लोगों के साथ संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। योगी सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उस बख्शा नहीं जाएगा।

बाल तस्करी और देह त्यापार पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, बोला... -इससे निपटने न्याय प्रणाली को और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, (ईएमएस)। देश में बाल तस्करी और देह व्यापार की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय को अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन तस्करी के पीड़ितों, विशेषकर नाबालिगों की गवाही को उचित महत्व और विश्वसनीयता दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अदालतों को तस्करी की शिकार किसी नाबालिग पीड़िता के साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय उसकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और कभी-कभी सांस्कृतिक असुरक्षा को

ध्यान में रखना चाहिए। पीठ ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि यदि पीड़िता किसी हाशिये पर पड़े, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े समुदाय से आती है, तो उसकी स्थिति और अधिक संवेदनशील हो जाती है। शीर्ष अदालत ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां लड़कियों की बाल तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के बयान को सामान्य अपराधिक मामलों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीठ के अनुसार,

तस्करी का शिकार बनी नाबालिग अक्सर भय, दबाव, सामाजिक कलंक और मानसिक आघात के कारण अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाती, जिसका असर उसके बयान में दिखाई दे सकता है। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसकी गवाही अविश्वसनीय है। अदालत ने जोर देते हुए

कहा कि पीड़ितों के साक्ष्य का न्यायिक मूल्यांकन संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को यह समझना होगा कि बाल तस्करी और देह व्यापार जैसे अपराधों में पीड़ित की स्थिति असमान शक्ति संतुलन, शोषण और मजबूरी से जुड़ी होती है। ऐसे में साक्ष्यों की तकनीकी कमियों पर अत्यधिक जोर देने से न्याय के उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि बाल तस्करी केवल एक आपराधिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट है, जिसके पीछे गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार जैसे कई कारण जुड़े होते हैं। अदालत ने उम्मीद जताई कि निचली अदालतें और जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएंगी।